महोदया, हमारे साथियों ने कश्मीर में लोकतंत्र की रक्षा के लिए और कश्मीर के विकास के लिए आगे आने वाले समय में जो कदम उठाने का सुझाव दिया है, मैं उनका पूरी तरह समर्थन करती हूं। महोदया, आज कश्मीरी नौजवानों के पास कोई कामकाज नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। यह ऐसा इलाका है जिसे रेल या दूसरे उपायों से जोड़ा नहीं गया है। कश्मीर के तीन हिस्से हैं—लद्दाख, कश्मीर वैली और जम्मू। जम्मू तक तो किसी तरह से जोड़ा हुआ है। लद्दाख तो दुनियां से बिल्कुल अलग ही हो जाता है अगर उसका आकाश मार्ग से न जोड़ा जाए। श्रीनगर वैली की भी यही स्थिति है। तो हमको जोड़ना होगा रेल मार्ग से, सड़क मार्ग से और आकाश मार्ग से भी ज्यादा सघन तरीके से जोड़ना देश के साथ, ताकि हमारे साथ उनका संबंध गहन हो, सुदृढ़ हो। साथ ही साथ रोजी, रोजगार का उपाय, पढ़ाई-लिखाई का उपाय, ग्रामों और कस्बों में स्कूल-कालेज का जाल बिछाना और छोटे-छोटे इलाकों में कुटीर उद्योगों का, उनका अपना कुटीर उद्योग है उस कुटीर उद्योग का भी सही मायने में मार्केटिंग का काम भी करना होगा। अगर नए कुटीर उद्योगों का विकास हो सकता है तो वह भी करना चाहिए। जैसे फल उनके यहां बहुत होता है। हम फूड प्रोसेसिंग इण्डस्ट्री के बारे में चर्चा करते हैं, फ्लोरिकल्चरण के बारे में चर्चा करते हैं। इनके विकास के लिए यह वहां संभव है। अगर वहां विकास होता है, इसका अगर वहां जाल बिछ जाता है तो बहुत से नौजवानों को काम मिल सकता है, रोटी-रोजगार मिल सकता है। जिसके हाथ में काम नहीं है तो उसके दिमाग में खुराफात आता ही है और बिना काम वाले लोगों को ही मिलिटेंट ने इस्तेमाल किया। जो मिलिटेंसी वहां बढ़ी है उसका एक कारण यह भी है। उनसे कहा गया कि यहां कुछ विकास होने वाला नहीं है जब तक अलग होकर स्वतंत्र कश्मीर का डिक्लेयरेशन नहीं करेंगे। इसको बढ़ावा दिया है। अब चुनाव के बाद यह प्रमाणित करना होगा तथा भारत सरकार को ज्यादा अनुदान, ज्यादा सहायता और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप करके कहना पड़ेगा कि आप हमारे हिस्सा हो, आपके सुख-दुख में हम भागी हैं। और अगर वह बकार रहेंगे तो उसके आंख से आंसू आएगा तथा वह फिर हथियार उठाएगा। तो हम उसके लिए प्रबंध करेंगे कि हथियार नहीं, हथियार फैंक कर मशीन चलाओ। यह बड़ा कठिन काम होगा। लेकिन मैं जानता हूं कि हमारी सरकार उसको करने के लिए कटिबद्ध है। मैं इन्हीं बातों के साथ, हमारी सरकार ने अब तक जो-जो कदम उठाए हैं मैं उनकी सराहना करते हुए इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहूंगी कि मुझे बताया गया है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर लोक सभा में कुछ और बिल के संबंध में वहां बिजी होने के कारण जवाब के लिए हमारे सदन में उपस्थित नहीं हो सकेंगे। तो क्या तब तक के लिए हम लिस्ट में जो दूसरा लिस्टेड बिजनेस है-शार्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, वह ले सकते हैं?

कुछ सम्मानित सदस्य: हां, ले सकते हैं।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: मैडम, यह तय कर दीजिए कि बाकी आईटम कब लिए जाएंगे। क्या फाइनेंस बिल पर आज बहस होगी, कल होगी। अगर आज होनी है तो कब होगी, क्योंकि डार्श ड्यूरेशन डिस्कशन के बाद यू०पी० का आएगा, कश्मीर का भी आएगा। फिर फाइनेंस बिल आज आएगा या नहीं? तो कुछ चीजें हाऊस को मालूम हो जाएं तो ठीक है। अभी तो फाइनेंस बिल की अमेंडमेंट भी सर्क्यूलेट नहीं हुई है। मेम्बर्स ने बहुत अमेंडमेंट दी हुई है। वह कब सर्क्यूलेट होंगी, क्या पोजिशन है?

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): मल्होत्रा जी, आपने जो सवाल उठाया है, मुझे ऐसा बताया गया है कि अमेंडमेंट्स काफी है और बाकी काम भी होना है। इसलिए शायद आज फाइनेंस बिल नहीं आ सकेगा।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: कब आएगा?

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): शायद कल के लिए रखा जाएगा।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: शायद नहीं, पक्का बताइए।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): कल होगा। आज उसके बारे में बाकी जो काम करना है वह हो जाएगा। तो कल आ ही जाएगा सदन के सामने। तो हम शार्ट ड्यूरेशन डिस्कशन लेंगे। श्री दीपांकर मुखर्जी।

SHORT DURATION DISCUSSION—

Revival of sick public sector fertilizer units vis-a-vis huge import of urea during the last five years

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): Madam, I am thankful to you and to the Chairman that when I had raised this issue as a Zero Hour submis-

sion on 2nd of August, I had been assured that there will be a full-fledged discussion on it. Though it is not a full-fledged discussion, at least there is a discussion on this issue. I am thankful that the Chairman has permitted this disucssion.

Madam, as I told on that particular day, to me and I think to all of us in this country Rs. 133 crores scam about the National Fertilizer Corporation is really a shameful thing for this country. Madam, we are importing fertilizers worth crores of rupees, while our fertilizer units, productive units are lying under-utilised or unutilised. I think this is a bigger scam than that. Madam, I would start my speech with imports. The issue is revival of six public sector fertilizer units vis-a-vis imports. I would give you the figures of import of fertilizers. The figures are like this during the last five years. In 1991-92, we imported 3.9 lakh tonnes of urea. In 1992-93, we imported 18 lakh tonnes of urea. In 1993-94, we imported 27 lakh tonnes of urea. In 1994-95 we imported 28.70 lakh tonnes of urea. And in 1995-96 we imported 37 lakh tonnes of urea.

In the first year of the five year period the import figure was 4 lakh tonnes. From 4 lakh tonnes, it has gone up to 37 lakh tonnes in the fifth year.

SHRI RAMDAS AGARWAL (Rajasthan) Madam, if you don't mind, I just want to correct the hon. Member's figure. The latest Annual Report for the year 1995-96 says..

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): अग्रवाल जी, मुझे लगता है कि आपकी टर्न आने वाली है।

श्री रामदास अग्रवाल: जी आने वाली है।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): तो उस समय अगर आप फिगर्स बताएं तो ठीक रहेगा।

Without any interruption to the hon. Member. That would be more appropriate.

श्री रामदास अग्रवाल: मैडम, फैक्टस, ही बहुत डिस्टर्टेड हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): कोई बात नहीं, जब आपकी टर्न आएगी तब आप बोलिएगा।

श्री रामदास अग्रवाल: उनके पास कौन सी रिपोर्ट है, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री रामदास अग्रवाल: चेन आफ थॉटस तो किसी भी स्पीकर की हमें हाउस में नहीं तोड़नी चाहिए।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Madam, it is very good that the hon. Member had raised this question. I am referring to the Unstarred Question No. 56, dated 11-7-1996.

From 1993-94 to 1995-96, that is, for the three years, the figure is 37 lakh tonnes. The source of figures for the years 1991-92 and 1992-93 is from the Fertilizer Association of India. It may be 35 lakhs or 37 lakhs. There might be a decimal change. The main thing is that we have imported fertilizers to the tune of so many lakhs of tonnes. I will give you the figures in financial terms for five years.

In 1992-93, it started from Rs. 764 crores, that is, 18 lakh tonnes of urea. In 1995-96, it ended with roughly Rs. 2,700 crores. This is in real terms. This is the quantity which we imported. This has increased. Against this, what is happening? The two public sector fertilizer companies namely, the Hindustan Fertilizer Corporation of India and the Fertilizer Corporation of India have become sick. Very shortly we are going to add another public sector fertilizer unit to this list, that is, the National Fertilizer Ltd. Another company is going to be added to the sick list. If you go through the Annual Report of the NFL, the scam-tainted corporation, it was the biggest profit earning company during the year 1995-96. My hon. friend, Mr. Agarwal was referring to this report. Before taxation, they earned Rs. 220 crores. Today, I got a fax message from the NFL. They are having units at Nangal, Panipat, Bhatinda, Vijaypur in Guna in Madhya Pradesh. This company is going to become sick. In June it had to stop its operation. They are having the working

capital problem. Its operation, its expansion at Vijaypur have been stalled because of this problem. Someone has done something wrong and the whole company is passing through this crisis. In the last five years—why five years, fifteen years—this is what happened. Now, this is the story of the last two years. These are the files containing the questions and answers on the revivial of the Hindustan Fertilizer Corporation and the Fertilizer Corporation of India. I have seen all the parliamentary records and evidence on these two companies. It is like the dribbling in the game of foot-ball. The Hindustan Fertilizer Corporation has four units in Durgapur, Barauni, Namrup and Haldia. The Fertilizer Corporation of India has four units, in Sindri, Ramagundam, Talcher and Gorakpur. Out of these eight units, unfortunately, seven are located in the eastern zone; barring Ramagundam.

Mantriji, would you please listen to me? No hurry. We have waited for fifteen years.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SHEES RAM OLA): I wanted to know the correct figures. Do not worry. I will reply and I will give you the correct figures. I was only collecting the correct figures.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: These are sick. These are to be revived. Why are these units sick? Again, if you go to the annual reports, you will find that these units are sick because of the ageing of the plants, old designs and other problems. They were designed in 60s, or 70s, about 20 years back! Normally, a fertilizer plant requires upgradation of technology and expansion. In most of these cases, the plants are age-old and the machinery are old. They require renovation, upgradation of technology and input of some capital. What has been the history of the one about which I raised an issue? In April, 1995, last year, there was a Cabinet decision. A decision was taken in principle by the Cabinet—this was intimated to the whole country—that there was a proposal to revive these units at a cost of Rs. 2200 crores. What would be the result of the revival which the Cabinet agreed to in principle? You would get 23 lakh tonnes of urea. If you revived these units for which Rs. 2200 crores was required, you would get 23 lakh tonnes of urea. That decision still remains unimplemented. Nothing has started. Why? Because there is no fund. Here is a country which could import urea worth Rs. 2700 crores, in one year, but could not decide where from Rs. 2200 crores would come so that these units could be revived and could produce 23 lakh tonnes of urea! It is not today's story. I have with me all the records. I know what reply is going to come. I have got the latest letter from the Minister in September, 96. I do not find any change. It is only a repetition. They are more or less tuned to this. In the case of the Hindustan Fertilizer Corporation units in Durgapur, Barauni and Namrup in West Bengal, Bihar and Assam, there was a proposal. Experts, foreign experts, were appointed—M/s Halder Topsoe, Italy. They had submitted a report. Foreign exchange was paid for consultancy. They submitted a report in April, 1988. The proposal for these units would have cost you Rs. 468 crores. But 10 lakh tonnes of production was guranteed by that company. They had guaranteed 9.90 lakh tonnes of production. If the renovation worth Rs. 460 crores was done. What has happened to that proposal? No one knows. After that, there is another report on the Haldia plant by M/s Toyo, Japan, and M/s Udhe, West Germany. They got Rs. 2 crores as consultancy fee. They have given a proposal for Rs. 500 crores which would give you four lakh tonnes of fertilizer nutrients. This was in 1988 or 1989. After that, in 1992, these two companies were referred to the BIFR. After 1992, all of us have been raising questions. Only one reply has been coming for years.

"This has been referred to BIFR. The BIFR will decide the outcome of these companies." I do not understand it. the

fertilizer pricing is considered as an administered price by the Government. The BIFR was not to decide the price of these products. It is not the BIFR which is sitting over it for four years. So, another *natak* is going on for four years. I am saying *natak* with a lot of pain. Ultimately, the BIFR will decide this issue. What has been happening in BIFR for four years? I have got all the proceedings for these eight units. The case goes to the BIFR. What do they say? They say: "What is your proposal? Govt. says "Give us some time. Give us some time." It went on from 1992 to 1995. So, when the proposal came in 1995, the Cabinet had decided to revamp these units. it was a Cabinet decision. And who were present there? A group of Ministers had approved it. Who had approved it? Who were there in the group of Ministers? Mr. Pranab Mukherjee, Dr. Manmohan Singh and Mr. P. Chidambaram. I am taking these names only because an economist like Dr. Manmohan Singh, who was the Finance Minister, was there. Mr. Pranab Mukherjee was there. Mr. P. Chidambaram was also there. After it has been agreed, from that time onwards, the only point which is being talked about is that funds are not available. It has been approved by the Cabinet. Wherefrom will the funds come? The funding source is not available. One source of funding is the financial institutions. The other source of funding is the public sector fertilizer companies like KRIBHCO, IFFCO and NFL also. So, investible surplus from these companies was to be invested.

AN HON. MEMBER: It is not a company.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: I Know it is not a company. It is a cooperative society. But 80 per cent equity is from the Government. (*Interruptions*) So, they could not invest the investible surplus even within this country. They had to go outside for investment. So, the investible surplus companies, who can invest here, is the source or the financial institutions is the source of money. These sources of money were not found and the Cabinet agreed in principle. Recently, the Ministry of Fertilizer has sent its latest reply in respect of the revival of these companies. Within these two years, the revival cost must have increased. But, what exactly are you trying to do? What is the planning of the Government on these units? What is the planning of the Government to cut down imports by reviving these units? Now, the exercise which is going on, relates to discussion with the FIs--ICICI and so on. They have again appointed another consultant to see the revival scheme, to examine the revival scheme which was approved by the Cabinet in 1995. Who are the experts in the ICICI and the IDBI who know more about the financial aspects than the experts like Dr. Manmohan Singh and Mr. P. Chidambaram? Should it be construed that this approval was given without assessing the revival possibility of the company? What is being checked now by the ICICI? My question to the hon. Minister is: "What is being checked now?" Does it mean that the revival scheme was not viable? Does it mean that the Cabinet had given the approval without assessing whether the scheme was viable or not? Is there a super-Cabinet who is going to review a revival scheme which was already approved by the Government? This is my first question. My second question is, when the symptoms are known, the treatment is known, when so many foreign experts have gone into this question, what are we waiting for? I want to know from the new Government whether this point has been discussed in the Cabinet or not. After the Cabinet decision in 1995, who has taken this decision that the scheme which had been santioned by the Cabinet, which was agreed to in principle by the cabinet in 1995, has to be reviewed by the financial institutions? Did it go to the cabinet before deciding that this would be reviewed? My third question is: "Are you committed to the revival of these fertilizer plants?" If you are committed, kindly give an assurance by

what time you will start the revival process. If you are not committed to their revival, then how are you going to tackle the tremendous regional imbalance which you have created in the fertilizer scenario?

I mean, the greatest injustice has been done to the eastern zone. There are several units. If you have to run a fertilizer company in the eastern zone in the way such companies in the northern zone and the western zone are run, you cannot find a single big fertilizer company in the eastern zone. What alternatives do you have to match these imbalances? It is not in the interest of the eastern zone only. Madam, if the fertilizers are coming from the western zone and the northern zone to the eastern zone, 35 per cent of transportation is done through trucks. Precious diesel is being wasted on this. how long can you have imports? What is your import perception for the next three-four years? Your ports will not be able to handle this much of imports of fertilizers. A lot of dribbling has been going on here. सर, बंगाल के फुटबालर्स की काफी रेपुटेशन है। वे ड्रिबलिंग करने में माहिर हैं, गोल नहीं कर पाते। दस साल से यह चल रहा है।

Because I know what reply is going to come. I know that it will be like this: "These things have been given, this has been studied by this, another committee has been appointed, another committee will look into it!" This dribbling has been going on for the last ten years in these units, but I hope that the new Government will once and for all stop this dribbling game and score the goal.

रिवाइवल होना है या नहीं होना है। होना है You cannot delay it. एक-एक साल में कॉस्ट बढ़ रही है। What is your time-frame? When are you going to declare a zero debt? Sir, this question was asked last year. One explanation or the other was given. Please don't quote BIFR when you are going to reply. That is enough, because BIFR said that Govt. had never given a scheme to the BIFR. Now don't bring BIFR into the pricture. If you have to run the units, say, "We want to run the units." This is what we want. BIFR will be with you; BIFR said, "We will be with you if you are really interested in reviving the sick units."

And my final question is: Are you going to include NFL also in these companies, another four units along with these eight units? What is the condition of the NFL? Is it going towards sickness? What are its operational problems? Is its expansion programme problem going on as it is? Let them come out with those problems. Let the Members also know, let the people also know that somebody or some individual is responsible for the scam, not the company. Why is this company having the problem of working capital? If the banks and the financial institutions are not giving the money, I request the hon. Minister to go and talk to the Finance Minister. So many checkings are done by the IDBI and the ICICI when fund is required for reviving a sick fertilizer unit. Where was the scrutiny when Rs. 133 crores were given without any guarantee? Is it only regarding these public sector units, that they are talking about all types of securities, whether they are viable or not? And are they so sure when they give the loans to private sector? Regarding the IDBI and ICICI, if the Finance Minister does not give you the figures, Mr. Minister, I will help you and give you the figures, how much outstanding arrears these banks are to recover; whether they are 800 crores or 900 crores. I would like to know how all the money was given by these institutions; for what purpose that was given. So far, we cannot accept this IDBI or ICICI as a super boss who will decide the destiny of this country, so far as the fertilizer scenario is concerned, so far as the urea scenario is concerned. It is the Government which has to take this decision and I don't believe that the two financial institutions which are under the control of this Government or the companies which are under the control of the Ministry of Fertilizers, KRIBHCO IFF-

CO and all that, can have their own say, so far as the revival of these companies is concerned. This is a national issue. This has to be addressed nationally. This has to be addressed within the shortest possible time so that we don't have another scam or a series of scams. This scam must be the tip of the iceberg. There may be many other scams like this if we do not stop imports by increasing our indigenous production. Thank you, Madam. (ends)

SHRI BRAHMAKUMAR BHATT (GUJARAT): Madam Vice-Chairperson, I would like to appreciate what the hon. Member, Mr. Dipankar Mukherjee, has suggested. He has suggested some measures for revival of the sick fertilizer units in the country. But what I feel is that the basic question which has to be considered is better management. You have to see whether the employees working in a particular organisation are doing their job; whether they are sincere to the organisation; whether they know that if the organisation earns money, they will get the money out of it; whether their attitude is that since it is a public sector company they just don't bother about what is going on in the organisation. We will have to consider that also. Mr. Mukherjee has referred to certain public sector companies, the Hindustan Fertilizer Limited, National Fertilizer Limited, Fertilizer Corporation of India, etc. All of them expect NFL are making losses all these years. I know that NFL was making profit for some time. But now it is not. The capacity utilisation of other public sector units ranges between 40% and 60%. It is not more than that. The question is: What is wrong with these units? My friend has referred to IFFCO and KRIBHCO. With all humility I submit to the august House that I know IFFCO very well because I was the Chairman of IFFCO from 1977 to 1981. IFFCO is in the co-operative sector. It is not a company. let us not commit a mistake. IFFCO which is in the co-operative sector is a challenge both to the public sector and to the private sector. No private sector company in the country can match IFFCO, nor can any public sector company match IFFCO. IFFCO is a challenge both to the public sector and to the private sector. What is the reason? the reason is that there is a thing known as "IFFCO culture". The man who created IFFCO, who nurtured IFFCO, is Mr. Paul Pothen. I submit that just like Mr. Kurien in the milk industry, Mr. Paul Pothen is there in the fertilizer industry. Today he is an international consultant. The capacity utilisation in different plants of IFFCO, whether it is Kalol or Phulpur or Amla or Kandla, is over 100%. The capacity utilisation at Kandla which is producing NKP fertilizer, which is popularly known as *bara-bathis sola*, is 120% to 125%. In a fertilizer unit whatever is produced above 75% or 80% is just profit and nothing else. My friend has said that it is given 20% equity by Government. But the Government is not obliging. IFFCO is giving crores of rupees in interest to the Government every year. I am not here to deal with only IFFCO. IFFCO had a lot of money and, therefore, it created KRIBHCO. KRIBHCO was created in 1980 with a capital of Rs. 800 crores. Today they are the largest fertilizer co-operatives. They are producing about 4,500 tonnes of urea per day and 2,700 tonnes of ammonia per day. IFFCO and KRIBHCO--my friend may be knowing this--are making a profit of more than Rs. 100 crores every year. My submission to the august House and the hon. Minister is, let us ask the man who is an international consultant, who is an Indian, who has done a great job in this country, what we should do to improve the performance of these public sector fertilizer companies.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: In the report which I referred to, M/s. Halder Topsoe had suggested 100% guaranteed production at Durgapur, Barauni and Namrup. This was done as per the suggestion of Mr. Paul Pothan. Mr. Paul Pothan had drawn the plans and he had identified the ageing of the plth

and the design deficiencies and he had suggested the name of M/s. Halder Topsoe. M/s. Halder Topsoe gave their report which envisaged an investment of Rs. 460 crores to Rs. 480 crores and over 10,00,000 tonnes of production. But that was not implemented. That is the problem.

5.00 P.M.

SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: read this in paper earlier. I read it in a newspaper because I was not in this House. This is my first session. I read in the newspapers that Shri Paul Pothen was appointed by the Government to head a Committee. Mr. Mukherjee must be mentioning about this Committee. My submission is, call Shri Paul Pothen again. Let us take his advice. It is in the national interest. I entirely agree with Shri Mukherjee. Every year the demand of urea is going up by 12 per cent to 15 per cent. Therefore, the import is bound to be there unless we see to it that our own units are working, at least, in the capacity utilisation of 80 to 90 per cent; otherwise, there is no way out. The import will continue and money will go out. Therefore, my submission is, the organisation which advise the African people and put up plants over there, the organisations to which the Middle East countries invite and put up plants in joint venture, why not take advantage of these people? The Government should see to it that they do not have allergy for anybody. Some Government plants are there. Let these plant be there. There is no objection to it. But when a man is available, a man with international prestige, let us call him. IFFCO and KRIBHCO which, in my view, are the best organisations in India which have international prestige, international connections, are invited by other countries to put up plants. As Shri Mukherjee has suggested, whatever is suggested by Shri Paul Pothen in his report, I sincerely believe that in the interest of the farmers of this country, in the interest of the agriculture of this country and in the interest of the Government itself, should be implemented. We should see to it that Shri Paul Pothen is asked to do some job over it and a good thing is done in this country which will be in the best interest of the country. Except this, I have nothing to say. I hope that the Government would consider it and do something so that we are able to reduce the import of urea and other fertilizers as far as possible.

श्री रामदास अग्रवाल: उपसभाध्यक्ष महोदया, मुझे आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। मेरा एक धर्म संकट है, राजस्थान से इकलौते मंत्री हैं जो इस विभाग में हैं और मुझे वह कहावत याद आती है, करे कोई और भरे कोई। इन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है। अगर फर्टिलाइज़र उत्पादन में नुकसान हुआ है, उत्पादन कम हुआ है, घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है और बेईमानी हुई है तो यह तो अभी आए हैं और जिन्होंने किया वह यहां से विदा हो गये। आज यहां कोई उनमें से बैठा हुआ भी नहीं है। महोदया, खाद उत्पादन कृषि उत्पादन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस देश के किसानों ने मन में जो संकल्प किया कि हम अपने पैरों पर खड़े होंगे अपने खाने के लिए हम स्वावलम्बी बन जाएंगे, मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि भारत के किसानों ने अपना संकल्प पूरा किया है। अनेक प्राकृतिक विपदाओं के बाद भी उन्होंने अपने संकल्प को पूरा कर के इस देश को खाने के लिए अनाज दिया है। हमने अपनी जनसंख्या में कमी नहीं की लेकिन इसके बावजूद भी भारतवर्ष के किसानों ने उनके पेट की पूर्ति का काम कड़े परिश्रम से किया और मंत्री भी उसी किसान समाज में से आते हैं। महोदया, जब हम सरकारी उपक्रमों के संबंध में चर्चा करते हैं तो वास्तव में दिल दहलने लगता है क्योंकि उनमें लगा हुआ रुपया इस देश की गाढ़ी कमाई का पैसा है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का यह है कि समाजवादी व्यवस्था के अन्तर्गत, राष्ट्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत एक लाख तीस हजार करोड़ रुपया हमने इन सरकारी उपक्रमों में लगाया आज जब हम देखते हैं कि इन उपक्रमों से हमें वापसी क्या मिलता है।

इस कैपिटल इन्वेस्टमेंट का लाभ इस देश को क्या मिल रहा है। तो सबके मनों में कई शंकाएं खड़ी होती हैं। आज मैं सरकार के सारे उपक्रमों की बात नहीं करना चाहता हूं। मैंने केवल रेफरेंस के लिए यह बात कही है। आज महोदया फर्टिलाइजर की बात है। इस क्षेत्र में कई अच्छे प्रतिष्ठान हैं सरकार के कार्पोरेट सेक्टर के। इसके पहले कि मैं उन प्रतिष्ठानों की चर्चा करूं जो नुकसान पर

नुकसान करते चले जा रहे हैं मैं उन सरकारी प्रतिष्ठानों और सहकारी विभाग, सहकारिता के आधार पर चलने वाले फर्टीलाइजर कारखानों के व्यवस्थापकों की सराहना भी करूंगा। मैं चाहता हूं कि ऐसा हो सके कि हम उन सबकी सराहना कर सकें। लेकिन ऐसा होता नहीं है।

महोदया, जिन कारखानों ने अच्छा काम किया उन्हें हमें धन्यवाद देना चाहिए। देश की गाढ़ी कमाई में से उन्होंने कमाई करके देश के धन में कुछ रुपया जोड़ा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है महोदया कि जब मंत्री बदलते हैं तो शायद सरकारी कारखानों की आमदनी पर भी उसका असर पड़ता है। मैं इसलिए आप से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जिस एन०एफ०एल० की हम चर्चा कर रहे हैं आप के ही आंकड़ों के अनुसार मंत्री महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1993-94 में एन०एफ०एल० ने 389.11 करोड़ का प्राफिट किया था। मुझे ऐसा लगता है कि उस समय कोई मंत्री और थे और 1994-95 में यह नफा, इसी कंपनी का, इसी व्यवस्था में, इसी प्रकार की व्यस्था करने वाले लोगों में, घटकर केवल 121.93 करोड़ रुपए रह गया। यह कहां चला गया था। क्या भाव घट गए? क्या बाजार घट गया था? मंत्री जी जवाब नहीं दे सके। बाजार बढ़ा था। दाम बढ़े थे फर्टिलाइजर के लेकिन इस नफा कमाने वाली कंपनी का नफा किनकी जेबों में चला गया यह सवाल तो यह देश जानना चाहेगा। यह पूछेगा देश। आखिर, अगर हम नफा कमाने वाली कंपनियों को इस प्रकार नोच लेंगे, निचोड़ लेंगे किन्हीं अपने आजू बाजू के लोगों के स्वार्थ के लिए तो फिर ये नफा कमाने वाली कंपनियां भी बरबाद हो जायेंगी। इनको भी कोई नहीं बचा सकता। इसलिए मंत्री महोदय मैं आप से एक बात साफ कह देना चाहता हूं कि इस बात की पूरी निगरानी होनी चाहिए कि जो उद्योग नफा कमाते हैं अगर गए वर्ष में उन्होंने नफा जितना कमाया, उससे अगर कम होता है तो उस बात की पूरी तरह से छानबीन होनी चाहिए। उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। उसका रिव्यू होना चाहिए। उसके ऊपर पूरी जांच होनी चाहिए कि नफा कम क्यों होता है। आखिर कुछ तथ्य उसमें से आने चाहिए।

लेकिन यह अचानक हो गया। जो मंत्री इस समय आए, नफा कमाने वाली कंपनियों का नफा कम हो गया। हिन्दुस्तान में जो इम्पोर्ट होनी चाहिए थी खाद उसकी मात्रा बढ़ती गयी। अभी हमारे दीपांकर जी ने आपके सामने कुछ तथ्य रखे। इसलिए मैंने आपके सामने निवेदन किया था कि उन तथ्यों में कुछ गलती है, कुछ कमी है। उनके तथ्य एक प्रश्न के उत्तर में हैं। मैं जो तथ्य दे रहा हूं वे, एनुअल रिपोर्ट 1995-96 की किताब जो मिनिस्ट्री आफ केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर, डिपार्टमेंट आफ फर्टिलाइजर ने निकाली है, उस आधार पर दे रहा हूं। महोदया, 1991-92 में हमारे देश में कंजम्प्शन था खाद का कुल मिलाकर 127.28 टन, प्रोडक्शन था 98.45 टन। इम्पोर्ट किया गया कुल 27.69 टन। 1992-93 मे 121 लाख टन का कंजम्पशन, प्रोडक्शन 97 लाख टन। इम्पोर्ट 29 लाख टन। 1993-94 में 123 लाख टन का कंजम्प्शन, प्रोडक्शन 90 लाख टन, घट रहा है और इम्पोर्ट 31 लाख टन, इंपोर्ट बढ़ रहा है। जैसे भारत में विदेशी मुद्रा बहुत इकट्ठी हो गई थी उसका क्या करें, शायद यह समस्या उस सरकार के सामने रही हो?...(**व्यवधान**) मैं टोटल दे रहा हूं।..(**व्यवधान**)

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: I gave the urea figures.

SHRI RAMDAS AGARWAL: I am sorry. I am not contradicting your figures...(*Interruptions*)

नहीं उसके अलावा भी है। 1994-95 में मैडम, 135 लाख टन का कंजम्प्शन था, उत्पादन 104 लाख टन हुआ और 29 लाख टन इंपोर्ट हुआ। अब आप आगे देखिए कि मंत्री के आने से क्या चमत्कार होता है या मंत्री के दखल से, अब हमारे माननीय मंत्री शीश राम जी क्या चमत्कार दिखायेंगे यह 1996-97 में पता लगेगा, लेकिन 1995-96 में कंजम्प्शन 146 लाख टन दिखाया गया। कितना हुआ मुझे नहीं पता। प्रोडक्शन 113 लाख टन हुआ और इंपोर्ट 40 लाख टन अच्छा इसमें भी एक और गड़बड़ है जो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 1993-94 में हमने 31 लाख टन ,टोटल फर्टिलाइजर इंपोर्ट किया उसकी कीमत 1 हजार 30 करोड़ रुपया थी। आप जरा गौर करें मुझे इसका जवाब चाहिए कहीं मैं गलत हूं तो मैं मंत्री जी से उसका जवाब चाहूंगा। 1994-95 में हमने 29 लाख टन इंपोर्ट किया और उसकी कीमत 1785 करोड़ रुपया हो गई। एक लाख टन कम इंपोर्ट किया और 750 करोड़ ज्यादा। अब यह मेरे समझ में नहीं आता कि क्या वजह है? इतना दाम बढ़ गया इंटरनेशनल मार्केट में या और कुछ कबाड़ा हो गया, क्योंकि आगे चल कर यूरिया में जो कबाड़ा हुआ तो इसी तरह से धीरे-धीरे होता गया। चोरी धीरे-धीरे की जाती है, जैसे प्रेम धीरे-धीरे किया जाता है वैसे चोरी भी धीरे-धीरे करते हैं। चोरी करते-करते-करते, जब उसको यह लगता है कि यहां बहत कुछ गुंजाइश है तो महोदया, चोरी करने वाला यहां

तक हो गया कि 133 करोड़ रुपया विदेशों में भेज दिया विदेशी मुद्रा के मार्फ़त और यूरिया आना था, अभी तक तो नहीं आया। यह हिंदुस्तान में ही हो सकता है इस प्रकार का महा घोटाला, इस प्रकार का भ्रष्टाचार, इस प्रकार की लूट और इस प्रकार की हाथ की सफाई, शायद बिहार में हो सकती होगी या बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री की हो सकती होगी?...(**व्यवधान**) जी हां, लगा रहता है इसलिए मैं कह रहा हूं 133 करोड़ रुपये का भूत आपके यहीं पर पैदा हुआ था। ...(**व्यवधान**) उस भूत से मुक्ति तो आप लोगों को पानी चाहिए थी, मुझे भूत के बारे मे आप क्या बता रहे हैं। ...(**व्यवधान**) में बिहार के नाम पर बात नहीं कर रहा, में आप को केवल एक रेफ्रेंस दे रहा हूं, महोदया, कि आखिर 133 करोड़ रुपये का इतना बड़ा घोटाला हो जाए और किसी को लज्जा नहीं आती। मुझे आश्चर्य होता है। मुझे कई बार जब अखबारों में पढ़ने को मिलता है, जब घोटाला एक, घोटाला दो, घोटाला तीन, घोटाला चार, ऐसे कई घोटाले पढ़ता हूं तो कोई ऐसा घोटाला नहीं आता जिसमें राव नाम के शब्द का उपयोग नहीं हो। चाहे गैस का हो, चाहे फर्टिलाइज़र का हो, चाहे बैंक का हो, राव तो कहीं न कहीं है। अभी क्या हो रहा है, आखिर इस देश के अंदर इस प्रकार के घोटाले कब तक बर्दाश्त किए जाएंगे? महोदया, मैं घोटालों की चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक बात और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमारे जो घाटा करने वाले उद्योग हैं, आप जरा उनका नक्शा देखिए। लॉस मेकिंग यूनिट्स का जिन्होंने चर्चा अपने ही इस रिपोर्ट के अंदर एफ०सी०आई० 1989-90 में घाटा शुरू हुआ। 146 करोड़ का और 1995-96 में बढ़ते-बढ़ते 426 करोड़ का हो गया। तो घाटा बढ़ रहा है। फिर एच०एफ०सी० में 89-90 में 169 करोड़ का घाटा हुआ। उसमें धीरे-धीरे तरक्की हुई। समाजवाद लाया गया था, बाद में लिबरलाइजेशन लाया गया। समाजवाद के नाम पर कारखाना लगाया गया था, लिबरलाइजेशन के नाम पर उनके बजटरी सपोर्ट बंद किए गए और लिबरलाइजेशन के नाम पर 169 करोड़ रुपए का लास 468 करोड़ रुपए में बदल गया। इस प्रकार यह घाटा बढ़ता जा रहा है। यह तीन कंपनियों का घाटा है—एफ०सी०आई० का 2900 करोड़ रुपए टोटल क्युमुलेटेड लॉस अप टू लास्ट इयर, एच०एफ०सी० का 3100 करोड़ और पी०डी०एल० का 100 करोड़ रुपए का और कुल 6100 करोड़। यह मैंने इन तीन कंपनियों का अब तक का क्युमुलेटेड लॉस बताया। महोदया, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कंपनीज लॉस में क्यों जाती है? मैं जानता हूं कि कंपनियां घाटे में होती हैं। सरकारी कंपनियां दुबली होती जाती हैं और उनके ठेकेदार मोटे होते जाते हैं। उनमें काम करने वाले कर्मचारियों के चेहरों पर चमक आ जाती है। उससे संबंधित मंत्री घाटे करके चले जाते हैं और अफसर ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर किसी की जिम्मेदारी नहीं रहती। महोदया, मैं पूछना चाहूंगा कि यह क्रम इस देश के अंदर कब तक चलेगा? इसे रोकने का संकल्प भी तो होगा या हम इसे रोकना नहीं चाहते और बर्बादी चाहते हैं। अब देश बर्बाद हो चुका है और इससे ज्यादा बर्बादी यह देश टॉलरेट नहीं करेगा। इससे ज्यादा भ्रष्टाचार अब इस देश को स्वीकार्य नहीं होगा। महोदया, अब यह देश ऐसे लोगों को कभी भी क्षमा नहीं करेगा जो सीधे-का-सीधा रुपया ट्रांसफर कर के दलाल और कमीशन खा जाए और माल देश में आए ही नहीं। अब यह नहीं चलेगा और जो यह चलाने की कोशिश करेगा, जनता उससे बदला चुकाएगी। अब जनता जागरूक है, जनता चेती हुई है। जनता के अंदर रोष है, गुस्सा है और यदि हमने समय रहते चेतना नहीं लाई, परिवर्तन नहीं लाया तो फिर निश्चित रूप से मानकर चलिए कि लोग भ्रष्टाचारियों से किस प्रकार से गिन-गिन कर हिसाब चुकाएंगे हिंदुस्तान की गलियों में, यह मैं नहीं जानता? यह मैं चेतावनी देना चाहता हूं जिसमें हम सब शामिल हैं।

श्री रामदेव भंडारी: खुद भी लीजिए।

श्री रामदास अग्रवाल: मैं कह रहा हूं "सब" और सब का मतलब शायद आप हिंदी में जानते हैं। आप ही के लिए नहीं कह रहा हूं, बंगाल के लिए भी कहा है मैं ने।

महोदया मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कंपनियां लगातार नुकसान कर रही है, अब उनका हम क्या करें? हम उनको जिलाएं या दफनाएं, यह सवाल हमारे कम्युनिस्ट भाइयों के दिमाग में बड़ा गर्म रहता है। आप इस बात का जवाब दें कि जो कंपनी लगातार लॉस करती चली जाएगी, उसकी सब्सिडी 95-96 में 4300 करोड़ रुपए थी और 96-97 मे 4500 करोड़ रुपए मिलेगी? महोदया...

श्री नीलोत्पल बसु (पश्चिमी बंगाल): मैडम, अगर वह ईल्ड करें तो मैं एक सवाल पूंछना चाहता हूं?

श्री रामदास अग्रवाल: महोदया, मैं अपनी बात पूरी कर दूं, उसके बाद अगर आप आदेश करेंगी तो मैं ईल्ड करूंगा।

श्री नीलोत्पल बसु: टिस्को भी पब्लिक सैक्टर कंपनी है।

श्री रामदास अग्रवाल : मैं ने पहले ही उन कंपनियों की सराहना की है जो कि अच्छा काम कर रही हैं।

श्री नीलोत्पल बसु: मैडम, अच्छी कंपनी भी होती है, बुरी कंपनी भी होती है। अच्छा पब्लिक सैक्टर भी है और बुरा पब्लिक सैक्टर भी है। अब यह गलत तरीके से... **(व्यवधान)**...

श्री रामदास अग्रवाल : महोदया, मैं जो कह रहा हूं उसे मेरे मित्र शायद सुन नहीं रहे या समझ नहीं रहे हैं। मैं ने पहले ही कहा कि जो कंपनियां अच्छा काम करती हैं, उनको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं।

श्री नीलोत्पल बसु: आप समझते हैं कि आप जो बोल रहे हैं, वह ठीक है और दूसरे जो बोल रहे हैं वह ठीक नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

श्री रामदास अग्रवाल: नहीं, ऐसा मैं ने कुछ नहीं कहा। आप की तरफ से दीपांकर जी अपनी बात रख चुके हैं, इसलिए आप उसकी चिंता न करें। वह सक्षम हैं आप की बात रखने मे क्योंकि वह भी कम कम्युनिस्ट नहीं है।

श्री नीलोत्पल बसु: मैं उनकी अक्षमता के बारे में नहीं बता रहा हूं। आप जो बोल रहे हैं, उस बारे में बता रहा हूं। ...**(व्यवधान)**..

श्री रामदास अग्रवाल: उनके रिवाइवल के लिए क्या करें ? जैसा मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया कि हमने 95 के अप्रैल में यह तय कर लिया था कि तीन कंपनियों के रिवाइवल के लिए 2201 करोड़ रुपया देंगे, अच्छी बात है, दीजिए, लेकिन यह 2201 करोड़ रुपया आया नहीं। मंत्रिमंडल के फैसले के बाद भी नहीं आया। उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मदद नहीं मिली। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि होना चाहिए। डेढ़ साल तक, पौने दो साल तक निर्णय नहीं हुआ, तब उन मजदूरों का क्या हुआ? वहां पर काम करने वाले लोगों का क्या हुआ? फिर यह 2201 करोड़ रुपया रिवाइवल के लिए उस वक्त सोचा था, अब जो प्राइस ऐस्केलेशन हुआ उससे कितना रुपया बढ़ गया? मैं निश्चित मानता हूं कि कम से कम 500 से 800 करोड़ रुपया बढ़ गया। अब 3000 करोड़ रुपया चाहिए आपको और अगर एक साल बाद आप निर्णय लेंगे तो आपको 3500 करोड़ रुपया चाहिए होगा। निर्णय लेने के बाद इंप्लीमेंटेशन का सवाल, यह सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है।

महोदया, केवल निर्णय लेने से काम नहीं होता। निर्णय लेने से मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल जाएगी, वे कारखाने चालू नहीं हो जाएंगे। इसलिए उन कारखानों को अगर चालू करना है तो यह जो सरकार ने निर्णय किया था, उसको तुरन्त लागू करवा दें। यह निर्णय क्यों लागू नहीं हुआ, उसके कारण में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स ऐसे सरकारी कारखानों को मदद देने में हिचकिचाती है। यह स्वाभाविक बात है क्योंकि बैंक अगर पैसा देंगे तो उनको डर लगता है कि यह अगर 6100 करोड़ रुपया हजम कर गए, लूट लिया या नुकसान हुआ आगे ऐसा नहीं होगा इकी क्या गारंटी है, कौन गारंटी देगा। इसलिए उनके रिवाइवल के लिए आपके सामने दोनों तरफ से सवाल है। मैं भी मजदूर भाइयों के प्रति आप जितनी ही सहानुभूति रखता हूं। मैं चाहता हूं कि काम न छीना जाए, उनके रोजगार पर आंच नहीं आनी चाहिए, लेकिन सवाल सीधा-सीधा यह है, रोजगार देना एक आवश्यकता है, लेकि क्या कारखानों को चालू कर उन कारखानों को फिर से नुकसान और फिर से नुकसान देने केलिये या हम हम बाध्य हैं? इस पर भी हमें विचार करना होगा।

महोदया, संसद को इन दोनों पक्षों पर विचार करना होगा। संसद एक पक्ष से विचार नहीं कर सकता कि केवल एम्पलायमेंट के लिए हम कारखाने चलाते चले जाएं और उनमें नुकसान हो तो होने दें। यह लूट-खसोट मिटनी चाहिए। मैं भी एक उद्योग से संबंध रखने वाला व्यक्ति हूं। मैं जानता हूं, अगर घाटा होता है, काम करने से कोई नुकसान नहीं होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उद्योग फिर कमा लेगा, लेकिन उद्योग में अगर नौकरशाही ही उस उद्योग को चाटने लग जाएगी, खाने लग जाएगी, उसको नोचने लग जाएगी या उसको निचोड़ने लग जाएगी तो फिर वह उद्योग नहीं चल सकता। इसलिए पहले रिवाइवल आपको यह करना पड़ेगा, यह व्यवस्था करनी पड़ेगी, ऐसे प्रबंधक देने पड़ेंगे और उनके ऊपर यह बंधन देना पड़ेगा कि हम रुपया दे रहे हैं रिवाइवल के लिए रीवेम्पिंग के लिए और आपको यह करखाना चलाकर दिखाना पड़ेगा। अगर नुकसान हुआ तो तुम्हारे पेट में से भी निकाला जा सकता है। यह आपको करना पड़ेगा वरना यह बड़ी अजीब मुसीबत हो गई है कि करोड़ों के घाटे हो जाते हैं और लोग छीनकर

होकर चले जाते हैं घरों में। उनके घरों में बहुत बड़े-बड़े, अफसोस जैसे की सुखराम जी के घरों में मिले, वैसे ही उनके घरों में भी मिल सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संसद को इस बात पर विचार करते वक्त पहले यह गारंटी लेनी पड़ेगी कि जो नुकसान में चलने वाले उद्योग हैं, उनके ऊपर जो प्रबंधक बैठाए जाएंगे, जो प्रबंधन तय किए जाएगा, मैनेजमेंट तय किया जाएगा, उसकी चोटी किसके हाथ में होगी। आप शीश राम जी के हाथ में उनकी चोटी दे दीजिए, मुझे विश्वास है कि वह हिलने नहीं देंगे। लेकिन, शीश राम जी कितनेदिन रहेंगे? मुझे खुद पता नहीं, उनको भी नहीं पता। सवाल यह आ जाता है कि ब्यूरोक्रेसी तो परमानेण्ट है, ट्रांसफरेबल है और शीश राम जी तो भले ही ट्रांसफर पार्टी में हो जाएं, कांग्रेस से तिवारी-कांग्रेस में आ जाएं या तिवारी-कांग्रेस से और कहीं चले जाएं, रहेंगे राजनीति में ही, लेकिन ब्यूरोक्रेसी, एफ०सी०आई० न सही एन०एफ०एल० ने सही एन०एफ०एल० न सही एम०एम०टी०सी० सही। वह कहीं चला जाता है, उसकी मौज-मस्ती में कोई कमी नहीं होती। जब भी हम इन बातों की चर्चा करते हैं, महोदया, तब यह सवाल हमारे आता है कि इतने हजारों करोड़ रुपए का घाटा होता चला जाता है। उसको रोकने के लिए कोई व्यवस्था, कोई मैकेनिज्म, कोई इस प्रकार के कठोर अनुशासन की व्यवस्था की जाए ताकि इस प्रकार का घोटाला न हो पाए, इस प्रकार की लूट न हो पाए। और मेरे कम्युनिस्ट भाई भी इस बात से सहमत हैं, वे भी इस बात को जानते हैं कि अगर लूटा जाएगा तो वह कारखाना नहीं चल सकता। मजदूर का हित उसमें नहीं है, मजदूर का हित कारखाना चलने में है, उसके नफा कमाने में है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो घाटे वाले यूनिट्स हैं उनके रिवेम्पिंग के लिए सरकार यदि यह निश्चय करती है कि पैसा दिया जाए, देना चाहिए, मैं भी प्रथम दृष्टया इस बात को स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन साथ मे मैं यह शर्त लगाना चाहता हूं कि अगर आप इस प्रकार की रिवेम्पिंग की व्यवस्था करते है तो रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था नहीं चलेगी। रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था में जो आप रिवेम्पिंग के लिए पैसा देंगे, फाइनेंशियल ईस्टीट्यूशन पैसा देगी, वह भी बट्टे खाते चला जाएगा, वह भी बटटे में चला जाएगा। इस देश के अंदर भ्रष्टाचार रूपी जो सुरसा का मुंह है, उसा कोई साइज नहीं है, उसका कोई साइज़ तय नहीं । रामायण काल मे तो 100 मीटर तक मुंह फाड़ने के बाद सुरसा के मुंह का साइज़ खत्म हो गया था लेकिन यह भ्रष्टाचार का जो सुरसा का मुंह है, हजारों करोड़ खाने के बाद भी उसका तो मुंह बड़ा ही होता दिखाई देता है, छोटा होता दिखाई नहीं देता। इसलिए इस सुरसा के मुंह पर आप क्या प्रतिबंध लगाएंगे ताकि इस देश में भ्रष्टाचार घटता चला जाए? इस पर रोक लगाने की जब तक आप व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक रिवाइवल, रिवेंपिंग की सारी व्यवस्थाएं बेकार साबित हो जाएंगी। हम केवल पैसा इधर से निकाल कर फिर कुए में डाल देंगे। फर्टिलाइज़र तो आखिर इस देश का जीवन और प्राण है, उसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा।

मैं अंत में एक बात और कहता हुआ अपनी बात समाप्त करूंगा कि जो नए प्लांट लग रहे है, कोई 1000 करोड़ का लग रहा है, कोई 900 करोड़ का लग रहा है, कोई 500 करोड़ का लग रहा है, महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से और सरकार से आग्रह करना चाहता हूं और यह मांग करना चाहता हूं कि उन सब प्लांट्स का एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बना दिया जाना चाहिए, कोई ऐस्केलेशन नहीं दिया जाना चाहिए। अगर किसी प्लांट को 1997 में आरंभ होना है तो उस प्लांट को 1997 में आरंभ होना ही होगा और अगर नहीं होता है तो वहां के जो प्रबंधक लोग हैं, उनको इसके लिए जिम्मेदार बनाए, वरना यह ऐस्केलेट होता रहता है,कॉस्ट बढ़ जाती है और कास्ट बढ़ जाती है तो बजट के लिए आता है, सरकार का निर्णय होने में विलंब होता है और फिर वह प्लांट इकॉमिकली वॉयबल नहीं रहता है। ये स्थितियां बड़ी विचित्र बनती जा रही हैं धीरे-धीरे इस देश के अंदर। मुझे याद है राजस्थान नहर का जब पंडित नेहरू जी ने उद्घाटन किया था तो वह 57 करोड़ की थी कुल मिलाकर और आज हम उसके ऊपर 1500 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं और वह अभी तक पूरी नहीं हुई और यह योजना पूरी होनी थी दो पंचवर्षीय योजनाओं में लेकिन वह चलते-चलते 1997 तक आठवीं योजना तक चली। आप कोई पावर प्रोजेक्ट लगाते है, उसमें भी, महोदया, यही होता है। मैं धौलपुर पावर प्रोजेक्ट का उदाहरण देना चाहता हूं। 700 मैगावाट का धौलपुर पावर प्रोजेक्ट है, उस समय सिर्फ ढ़ाई करोड़ रुपया प्रति मेगावाट कास्ट आती थी आज वह साढ़े चार करोड़ हो गई। हम केवल निर्णय करने में विलंब करते हैं, इसके कारण कॉस्ट ऐस्केलेट हो जाती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन प्लांट्स के बारे में मंत्री महोदय आपने कहा है कि 1997 में उनका प्रोडक्शन आएगा या 1998 में आएगा, उनमें आप यह बाध्यता पैदा करिये कि वह ऐस्केलेट नहीं होगा, टाइम एक्सटेंशन नहीं होगा,

रुपए में बढ़ोतरी नहीं होगी वरना वह कांट्रेक्टर और वहां के लोग मौज मारते जाएंगे और आपका प्लांट 1997 के बजाए शायद 21वीं शताब्दी में प्रारंभ होगा और यह देश के लिए फिर एक दुर्भाग्य होगा। आप अगर कुछ दिन के लिए आए हैं तो आप कुछ चमत्कारी परिणाम दिखाइए।

श्री शीश राम ओला: आपको क्या तकलीफ है हमसे?

श्री रामदास अग्रवाल: मैं चाहता हूं कि आप बहुत दिनों तक रहें। मैं यह इसलिए चाहता हूं कि क्योंकि आप मेरे राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। ...**(व्यवधान)**..,मैं चाहता हूं कि वे बहुत दिन रहें। बहुत दिन रहकर वे बहत कुछ काम करें। वे मेरे प्रान्त के इकलौते मंत्री हैं, मैं क्यों नहीं चाहूंगा।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): अग्रवाल जी, आप काफी बोल चुके हैं, अब समाप्त कीजिए। आप अच्छे मित्र नज़र रहीं आते मंत्री जी के।

श्री रामदास अग्रवाल: महोदया, मैं समाप्त कर रहा हूं। आपने जैसे ही मेरे ऊपर दृष्टि डाली, मैं समझ गया कि मुझे खत्म करना है।

मैं अन्त में केवल तीन बातें कहना चाहता हूं। पहली बात यह है कि फर्टिलाइज़र कारखानों को अगर आप रुपया देकर, बजट्री सपोर्ट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स से पैसा देकर, रिवेम्प करने का निर्णय कर चुके हैं, उसको इम्पलीमेंट करिए लेकिन साथ में जो मैंने शर्त लगायी है, उसको सख्ती से मनवाइये। शर्त मेरी यह है कि उनका रिवाइवल होने के बाद घाटा नहीं होगा, इसकी कोई गारण्टी बताइए। यह देश आपको याद रखेगा, किसान आपको याद रखेगा, आप ऐसी कोई व्यवस्था कीजिए। दूसरा मेरा निवेदन है कि जो प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है, उनका टाइम बाउंड प्रोग्राम जो आपने बना रखा है, उसमें गड़बड़ मत होने दीजिए। उसमें ढिलाई मत आने दीजिए। उसमें एक्सटेंशन और एस्केलेशन रोक दीजिए कि किसी हालत में नहीं होगा। इतना कर दीजिए। हमें किया है राजस्थान में। हमने कह दिया था कि पी०डब्ल्यू०डी० के अंदर कोई भी एस्केलेशन नहीं होगा और कोई पीरियड एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। हमने यह करके देखा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक्सटेंशन और एस्केलेशन रोक दीजिए।

महोदया, तीसरी बात यह है कि जो कारखाने नुकसान में चल रहे हैं, उनका रिव्यू होना चाहिए। मैं एक्सपर्ट धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। महोदया, आंकड़े चाहे दीपांकर मुखर्जी के हों या रामदास अग्रवाल जी के हों, उन आंकड़ों से एक बात साफ हो जाती है कि साल-दर-साल करोड़ों रुपए की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा हमको फर्टिलाइज़र आयात करने के लिए, यूरिया आयात करने के लिए खर्च करनी पड़ती है।

महोदया, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और हमारी अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर निर्भर करती है। अग्रवाल साहब ठीक कह रहे थे कि भारत के किसानों ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने में काफी श्रम किया है और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महोदया, भारत के किसान यह चाहते हैं कि जापान की तरह कमेटी में अभी आया हूं इसलिए मुझे जानकारी नहीं है कि उसमें रिव्यू किस प्रकार किया जाता है। आगे जब मैं कमेटी में बैठूंगा तो मुझे जानकारी होगी। लेकिन मेरा निवेदन है कि नुकसान में चल रहे कारखानों का रिव्यू होना चाहिए और नफा करने वाले कारखानों का भी रिव्यू होना चाहिए। इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

श्रीरामदेव भंडारी (बिहार): महोदया, मैं आपको आधुनिक तकनीक का कृषि में प्रयोग करके कृषि उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ाया जाए और अधिक उत्पादन करने के लिए फर्टिलाईजर की, खाद की, यूरिया की आवश्यकता होती है, यह हम सब जानते हैं। महोदया, मैं बिहार से आता हूं। हर साल जब कृषि का मौसम आता है तो यूरिया की कमी का मामला बिहार के लोग इस सदन में उठाते हैं। महोदया, बिहार में खाद के 2 बड़े-बड़े कारखाने हैं—एक है सिन्दरी का कारखाना और दूसरा है बरौनी का कारखाना। सिन्दरी के कारखाने को "मदर प्लांट" कहा जाता है। महोदया, 80 के दशक में इसका माडर्नाइजेशन हुआ, तब यहां उत्पादन ठीक ढंग से हो रहा था। आज इस कारखाने में पुरानी मशीनरी को बदलने की जरूरत है। उसी तरह बरौनी के कारखाने को भी रि-वैंप करने की जरूरत है, मोडर्नाईज करने की जरूरत है। महोदया, नयी तकनीक का प्रयोग करके और नयी-नयी मशीनें लगाकर इन दोनों कारखानों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है।

महोदया, 1995 के अप्रैल माह में कैबिनेट ने कई योजनाएं इन दोनों प्लांट्स को सुधारने के लिए बनाई थीं मगर उनका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सका। दूसरे जो फर्टिलाईजर प्लांट्स हैं, उनके लिए भी योजनाएं बनी हैं

लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। महोदया, यह बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। अब हम यह बरदाशत नहीं कर सकते कि इतनी भारी राशी हम फर्टिलाईज़र के आयात में लगाएं।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने देश में जो फर्टिलाइजर प्लांट है उनको माडर्नाइज करें, नई तकनीक का विकास करें और अपने देश के जो प्लांट है वह जब पूरा उत्पादन करेंगे तो मैं नहीं समझता कि विदेशों से इतनी भारी मात्रा में हमें खाद या यूरिया आयात करने की आवश्यकता पड़ेगी। मैं एक बार पुनः मंत्री महोदय से निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं और इस सदन ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं माननीय श्री दीपांकर मुखर्जी द्वारा, भट्ट साहब द्वारा और अग्रवाल साहब द्वारा, मैं उससे सहमत हूं और सरकार शीघ्र ही इस दिशा में कोई कार्रवाई करे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI S. MUTHU MANI (Tamil Nadu): Thank you, Madam, Vice-Chairman.

I rise to support the demand made by my learned colleague, Shri Dipankar Mukherjee, and other hon. Members of this House.

At the outset, I must say the Government at the Centre did not live up to the expectations of the farmers and the workers of this country. On the one hand, the farmers are suffering for want of fertilisers at affordable prices. On the other hand, the public sector fertiliser units are made to fall sick, with the intention of closing them down, thus throwing thousands of workers out of employment.

The Hindustan Fertiliser Corporation Limited and the Fertiliser Corporation of India have been facing a crisis ever since they were declared sick, for various reasons. In April, 1995 the Central Government had approved, in principle, revival packages for these two sick fertiliser-producing public undertakings.

The Barauni, Durgapur and Namrup units of the Hindustan Fertiliser Corporation Limited, and the Sindri, Ramagundam and Talcher units of the Fertiliser Corporation of India, were to be revamped in a limited way. A fresh investment of Rs. 464.93 crores for the HFCL units and Rs. 1,786.20 crores for the FCI units was decided upon by the Government.

The Government later said that funds could not be tied up and, ultimately, set up an expert committee to reformulate the revival packages from the standpoint of funding by the financial institutions. But unfortunately, no step has been taken so far to revive these units. As it is right from the days of privatisation, the workers were under the grave threat of retrenchment. In spite of the assurance by the previous Government, workers were retrenched in several public sector units, though under different names.

Here is a peculiar situation, Madam. The Government is importing urea and other fertilisers by spending huge amount of foreign exchange. Yet it is not prepared to revive these sick units. Urea is used to a very great extent by the farmers throughout the country. The public sector units account for 43.21 per cent of the total urea production in the country. Even those units declared sick produce 26.50 lakh tonnes of urea, accounting for 15.68 per cent of the total production. This clearly indicates that the country cannot afford to close down these fertiliser units just because there is alleged paucity of funds.

Madam, the average per-hectare consumption of fertiliser nutrients has increased from less than 1 Kg. in 1951-52 to about 74 kg. in 1994-95. Even this is said to be low, as compared to many countries. In India, urea is the main nitrogenous fertiliser, constituting about 60 per cent of the total fertiliser consumption in the country. But domestic industry is not able to meet the demand, compelling the Government to import urea. When urea does not reach the farmers in time because of the obstacles in import and distribution, it affects the crop yield and has grave repercussions on the economy. That is why we had decline in the output of foodgrains during the kharif season of 1995.

Even the Tamil Nadu farmers suffered last year because of non-availability of urea for the kuruvai season. The then Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Puratchi Thalaivi, had to take steps on a war footing to distribute the available urea to save the farmers and also to increase the yield. Then she had also taken up the matter with the Centre to import urea in time and not to discriminate against Tamil Nadu while distributing urea and other fertilisers.

Madam, the Centre should not sit pretty because the situation is very grave both for the farmers and workers. Therefore, on behalf of the All-India Anna DMK Party I urge upon the Centre to allocate the necessary funds for reviving all the sick fertiliser public undertakings without delay and revive them. Such a step will, besides boosting agricultural production, also save precious foreign exchange that the Government is spending for the import of fertilisers. This will further encourage our workers who, despite their hard work, are apprehensive of losing their jobs. I hope the hon. Minister, who is present here, will assure this House to this effect. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Hon. Members the Minister of Finance is here in the House and he would like to reply to the debate on Jammu and Kashmir. I think we should allow him to give the reply.

SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY (Andhra Pradesh): What about this topic, Madam?

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): After this. He will take only five minutes.

THE BUDGET (JAMMU AND KASHMIR), 1996-97

AND

THE JAMMU AND KASHMIR APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 1996—CONT'D

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF COMPANY AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Madam Vice-Chairperson, I apologise to hon. Members for not being present here when the discussion on Jammu and Kashmir took place. I was here when the first hon. Member started, but I had to go to the Lok Sabha because of two other finance Bills there. I share the concern of hon. Members for Jammu and Kashmir, but we all know that there are special reasons why that State suffered greatly, and I sincerely hope that the elections that are under way will mark a watershed and a new beginning for that State.

I do not claim any special credit for this Government for the decision to hold elections. Such a decision could not have been taken without the willing cooperation and support of all sections of this House and all political parties. We are in office today and, therefore, a decision of this nature had to be formally taken by the Government in office. But the Government readily acknowledges the cooperation received from all sections, all political parties, and the peaceful first phase poll in Jammu and Kashmir stands testimony to the correctness of that decision. I am sure that the conduct of free and fair elections in Jammu and Kashmir and the election of a State Legislature and the installation of a responsible Government in Jammu and Kashmir will send a signal to the whole world about India's commitment to democracy and India's commitment to bring peace in one of India's States and to respond to the aspirations of the people of that State.

Madam, I have very quickly perused the points made by hon. Members. In fact, some points made by Mr. Malkani, I believe, have been replied to by Mr.